



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ६]

शनिवार, जून ७, २०१४/ज्येष्ठ १७, शके १९३६

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषदमे दिनांक ७ जून, २०१४ ई. को. पुरःस्थापित निम्न, विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. IV OF 2014.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND
REVENUE CODE, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४ सन् २०१४।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६६
का महा.
४१।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१४, कहलाये।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९६६ की
महा. ४१ की धारा
१५० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १५० की, उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोड़े जाएँगे सन् १९६६
अर्थात् :— का महा.
४१।

परंतु, जहाँ भंडारकरण साधनों के उपयोग द्वारा धारा १४८-क के अधीन अधिकारों के अभिलेखों को अनुरक्षित किया जाता है, वहाँ यथाशिघ्र **तालुका** में **तहसीलदार** धारा १५४ के अधीन संसूचना प्राप्त करता है तो **तहसीलदार** कार्यालय का **तलाठी**, अधिकारों के अभिलेखों से वर्णित समस्त व्यक्तियों को या नामांतरण हित रखनेवाले नामांतरण रजिस्टर से और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित होने का विश्वास करने का कारण है, और लघुसंदेश सेवा या इलेक्ट्रानिक मेल या विहित किए जाए ऐसे किसी साधन द्वारा ग्राम के संबंधित **तलाठी** को भी भेजी जाएगी ; और ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर ग्राम का **तलाठी** तुरंत नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टी करेगा :

परंतु, यह कि, प्रथम परंतुक के अधीन यथा उपबंधित कोई संसूचना, भारतीय रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, सन् १९०८ १९०८ के अधीन रजिस्टर करनेवाले अधिकारी के सामने, जो व्यक्तिशः दस्तावेज निष्पादन करता है, उन का १६।
व्यक्तियों को **तहसीलदार** कार्यालयों के **तलाठी** द्वारा भेजी जाना अपेक्षित नहीं होगी ।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा १५४ यह उपबंध करती है कि, जब कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोगी भूमि पर जब सृजित, हस्तांतरित या किसी एक विलोपन के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज या किसी प्रभार या जिसके संबंध में अधिकारों के अभिलेख तैयार किये गये हैं। वह भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (सन् १९०८ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तब दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसमें भूमि स्थित है उस ग्राम के **तलाठी** और **तालुका** के तहसीलदार को उक्त संहिता के अधीन किये गये नियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और समय में सूचना भेजेगा। धारा १५० की उप-धारा (१) **अन्य बातों** के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि, **तलाठी** उक्त धारा १५४ के अधीन अर्जन या अन्तरण की किसी सूचना नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा। **तलाठी** महीने के दौरान दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से वह सूचना प्राप्त करता है तो वह अधिकारों के अभिलेख में हेरफेर प्रविष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। नामांतरण प्रविष्टि करने की प्रक्रिया में विलंब को कम करने और अधिकारों के अभिलेख समय में अधतन सुनिश्चित करने के लिए “इ-फेरफार” का संगणकीकृत कार्यक्रम राज्य में विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण राज्य में उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में पारदर्शकता लाने के लिये यह उपबंध करने के लिये प्रस्तावित किया गया है कि, जहाँ भंडारकरण साधन के उपयोग द्वारा धारा १४८ क के अधीन अधिकारों के अभिलेख बनाए रखे गये हैं और **तालुका** में **तहसीलदार** धारा १५४ के अधीन कोई सूचना प्राप्त करेगा। **तहसीलदार** कार्यालय में **तलाठी** अधिकारों के अभिलेख या नामांतरण में हितबद्ध किये जानेवाले नामांतरण रजिस्टर से प्रतीत होनेवाले सभी व्यक्तियों को और किसी अन्य व्यक्ति जो उसमें हितबद्ध किये जानेका विश्वास रखने का कारण है को और लघु संदेश सेवा या इलेक्ट्रॉनिक मेल या जैसा कि विहित किया जाए किसी ऐसे साधन द्वारा ग्राम के संबंधित **तलाठी** को भी भेजेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, ऐसा **तलाठी** नामांतरण रजिस्टर में तत्काल प्रविष्टि करेगा। यह भी प्रस्तावित करने के लिए उपबंधित किया गया है कि, ऐसी सूचना ऐसे व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (सन् १९०८ का १६) के अधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्ति के दस्तावेज निष्पादित किये गये हैं। इसलिए, सरकार महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १५० की उप-धारा (२) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ४ जून २०१४।

बालासाहब थोरात,
राजस्व मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रास्त है, अर्थात् :—

खंड २.—इस खंड के अधीन जिसका आशय महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १५० की उप-धारा (२) में निम्न परंतुक जोड़ना है, जिसमें राज्य सरकार को नियमोंद्वारा अन्य वैकल्पिक साधन विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा, धारा १५४ के अधीन **तालुका** में **तहसीलदार** द्वारा प्राप्त संसूचना, अधिकारों के अभिलेखों से वर्णित समस्त व्यक्तियों को या नामांतरण रखने वाले नामांतरण रजिस्टर से और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित होने का विश्वास करने का कारण है और लघुसंदेश सेवा या इलेक्ट्रॉनिक मेल से अन्यथा द्वारा ग्राम के संबंधित **तलाठी** को भी भेजी जाएगी।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपर उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ७ जून, २०१४।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।